

28 हजार वर्ग किमी में होगा एससीआर

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) लखनऊ सहित सात जिलों के 28,016 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। सरकार का दावा है कि एससीआर संतुलित और समावेशी विकास का मॉडल बनेगा। इसके लिए एक सप्ताह में कार्ययोजना तैयार की जाएंगी। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा और आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दो कमेटियां गठित की जाएंगी।

देश में पहली बार किसी राज्य में गठित होने जा रहे राज्य राजधानी क्षेत्र का लक्ष्य लखनऊ पर बढ़ती जनसंख्या से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, अनियोजित व क्षेत्र विशेष का विकास जैसी चुनौतियों का समाधान करना है। सरकार का दावा

एक सप्ताह में तैयार होगी कार्ययोजना, मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित होंगी दो कमेटियाँ

समन्वय, निर्णय व अनुश्रवण के लिए कमेटियां

एससीआर के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता वाली कमेटी में लखनऊ, कानपुर और अयोध्या मंडल के मंडलायुक्त, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, संबंधित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। कमेटियों का काम क्षेत्रीय योजना-कार्यक्रम तैयार करना, सभी जनपदों के लिए परियोजनाओं का निर्धारण, क्रियान्वयन व अनुश्रवण, परियोजनाओं का चयन व अनुमोदन, विकास के लिए प्राथमिकता प्रदान करना व जरूरी सहायता उपलब्ध कराना और वित्तीय प्रबंधन करना होगा। इसके अलावा हाई पावर कमेटी एससीआर के विस्तार के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श भी दे सकेगी।

एससीआर के जिले	जनसंख्या	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
लखनऊ	45,89,838	2,528
सीतापुर	44,83,992	5743
रायबरेली	34,05,559	4,609
बाराबंकी	32,60,699	4,402
उन्नाव	31,08,367	4,558
कानपुर नगर	45,81,268	3,155
कानपुर देहात	17,96,184	3,021

कुल जनसंख्या : 2,52,25,987 (2011 की जनगणना के अनुसार)

है कि एससीआर स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के वैश्विक मानकों के अनुरूप जीवंतता सूचकांक में अपनी खास जगह

बनाने वाला होगा। एससीआर आम आदमी को ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर विश्व स्तरीय अहसास कराने वाला होगा। इसमें लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव,

रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर व कानपुर देहात को शामिल किया जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय विस्तृत कार्ययोजना तैयार होने के बाद हो सकेगा।